ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन में नाबार्ड की डिजिटल पहल

डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने ईएमवी चिप और पीआईएन आधारित कार्ड जारी करने के लिए सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता देना आरंभ किया है. इन ग्रामीण संस्थाओं को एक सीमित अवधि के लिए 30 जून 2017 तक अधिकतम रु.25.00 प्रति कार्ड की सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्डों की स्वीकार्यता बढ़ाने और आर्थिक प्रणाली में कम नकदी के उद्देश्य से 5 टीयर और 6 टीयर क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन निधि से एक लाख गांवों में अधिकतम एक गाँव में दो पाइंट ऑफ सेल्स(पीओएस) लगाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.